



60 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाएंगे सीएम योगी

13 को बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित कर एक हजार रुपये मानदेय बढ़ाने की करेंगे घोषणा

- 2500 से बढ़कर 3500 रुपये होगा मासिक मानदेय, एकमुश्त 40 प्रतिशत की वृद्धि से सालाना मिलेंगे 12 हजार रुपये अतिरिक्त
- गृह विभाग से जुड़े ग्राम प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि से सरकार पर सालाना करीब 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय

समाचार सेन्टर संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों को योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में उनका मानदेय एक हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करेंगे। इससे ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 2500 से बढ़कर 3500 रुपये हो जाएगा। एकमुश्त 40 प्रतिशत की इस वृद्धि से प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी करेंगे। हाल के महीनों में रसोइयों, आंगनबाड़ी कर्मियों और पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सरकार ग्रामीण पुलिस व्यवस्था से जुड़े ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत देने जा रही है।

गृह विभाग से जुड़े ग्राम प्रहरी गांवों

में पुलिस के सूचना तंत्र की अहम कड़ी हैं। स्थानीय थानों से संबद्ध ये प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संधिगत गतिविधियों, आपसी विवादों और कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाते हैं। गांवों और थानों के बीच संपर्क बनाए रखने वाले ग्राम प्रहरी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित घोषणा से उनकी यह मांग पूरी होने की उम्मीद है। प्रदेश में इनकी अनुमानित संख्या 60 हजार है। इस आधार पर मानदेय में बढ़ोतरी से सरकार पर प्रतिमाह करीब सात करोड़ और सालाना 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए अनुपूर्व बजट में धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है।

मानदेय बढ़ाने के फैसलों की

अगली कड़ी- योगी सरकार ने हाल के महीनों में मानदेय पर कार्यरत



विभिन्न वर्गों की आय बढ़ाने के निर्णय लिए हैं। परिषदिय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली करीब 3.53 लाख रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में चार हजार और सहायिकाओं के मानदेय में दो हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रांतीय

रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता भी 500 से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। इसी क्रम में अब ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है।

सवा करोड़ से अधिक लोगों की

पेंशन भी बढ़ाने की तैयारी-मानदेय में वृद्धि के साथ ही सरकार सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैद्धांतिक सहमति के बाद वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और

दिव्यांगजन पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में इसे कैबिनेट के समक्ष लाए जाने की संभावना है। प्रदेश में 67 लाख से अधिक बुजुर्ग, 42 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएं और 12 लाख से अधिक दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रत्येक लाभार्थी को सालाना छह हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन मिल सकेगी।

सीएम योगी गोरखपुर से 9 लाख से अधिक किसानों को भेजेंगे 493 करोड़ की कृषि निवेश अनुदान राशि

बाढ़, ओलावृष्टि व चक्रवात से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी डीबीटी राशि

समाचार सेन्टर संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (12 अक्टूबर) को गोरखपुर की धरा से प्रदेश के किसानों को बड़ा आर्थिक संबल प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवात से प्रभावित प्रदेश भर के 9 लाख से अधिक कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि का अंतरण करेंगे। यह राज्यस्तरीय कार्यक्रम गोरखपुर स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होगा। इसके बाद सीएम योगी, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड एमएलसी चुनाव से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगी सहायता राशि- हाल के दिनों में प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी



नुकसान पहुंचा था। किसानों के नुकसान की भरपाई करने और उनके खेतों-खलिहानों में खुशहाली लौटाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री खुद डीबीटी प्रणाली के जरिए एक क्लिक से सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

कई जनप्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित- इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, प्रशासक जिला पंचायत साधना सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, सी.पी. चन्द, देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेन्द्र पाल

सिंह, बिपिन सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, इंजीनियर सरवन कुमार निषाद आदि उपस्थित रहेंगे।

शिक्षक मतदाता संवाद (रैली) में सीएम होंगे शामिल- गोरखपुर स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के बाद सीएम योगी, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड एमएलसी चुनाव से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे, यहां सीएम योगी शिक्षक मतदाता संवाद (रैली) को संबोधित करेंगे। शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के पक्ष में यह आयोजन रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होगा।

सीएम योगी की पहल से दिल्ली में सजी फिल्मी सितारों की रामलीला पहली बार बाल कलाकारों ने किया संपूर्ण रामायण का मंचन

नवरात्र विशेष
120 फीट की एलईडी स्क्रीन पर जीवंत हुई रामकथा, 40 भाषाओं में प्रसारण से 60 देशों तक पहुंचेगा प्रभु श्रीराम का संदेश
19 को सांसद रवि किशन निभाएंगे श्रीराम की भूमिका, अभिनेता अरुण बख्शी बनेंगे रावण
समाचार सेन्टर संवाददाता

अयोध्या। भारतीय संस्कृति और रामायण की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से शुरू हुई फिल्मी सितारों की रामलीला के आठवें संस्करण का शनिवार को दिल्ली के रफी मार्ग स्थित मावलंकर हॉल में शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिला। इस बार पहली बार बाल कलाकारों ने संपूर्ण रामायण का मंचन किया। तीन से 17 वर्ष तक के बच्चों ने अपने अभिनय से रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया। वहीं, 120 फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन और आधुनिक मंच सज्जा ने प्रस्तुति को आकर्षक स्वरूप दिया।

पहली बार बाल कलाकारों ने किया संपूर्ण रामायण का मंचन- रामलीला के इस संस्करण में पहली बार बच्चों को संपूर्ण रामायण के मंचन का अवसर मिला। तीन से 17 वर्ष तक के बाल कलाकारों ने श्रीराम जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक के विभिन्न प्रसंगों को संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति ने



सभागार में मौजूद दर्शकों का ध्यान खींचा और खुब तालियां बटोरें। मंचन में श्रीराम जन्म, विश्वामित्र आगमन, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, जनकपुर आगमन, सीता स्वयंवर एवं विवाह, राम वनवास, भरत मिलाप, चित्रकूट प्रसंग, शूर्पणखा प्रसंग, सीता हरण, किष्किंधा कांड, हनुमान मिलन, लंका दहन, रामसेतु निर्माण, रावण वध, अयोध्या वापसी और श्रीराम के राज्याभिषेक जैसे प्रसंग शामिल रहे। रामलीला के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक, महासचिव शुभम मलिक और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जतिन मलिक ने संयुक्त रूप से

बताया कि आयोजन में पहली बार बच्चों को अभिनय का अवसर दिया गया। उनके मुताबिक, हीरा पब्लिक स्कूल, एचएसवी ग्लोबल, पार्थ इंटरनेशनल, एचएसवी इंटरनेशनल और मिसरी देवी ज्ञान निकेतन स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस पहल के माध्यम से नई पीढ़ी को रामायण की शिक्षाओं, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अयोध्या की सांस्कृतिक

विरासत को वैश्विक मंच देने का

प्रयास- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से शुरू हुई इस रामलीला

के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकप्रिय कलाकारों की भागीदारी और आधुनिक प्रसारण माध्यमों के जरिए आयोजन को देश-विदेश के दर्शकों से जोड़ने की तैयारी है। आयोजकों के अनुसार, पिछले सात संस्करणों की मिली सफलता के बाद आठवें संस्करण को और भव्य बनाने की तैयारी की गई है। इस बार आकर्षक मंच सज्जा और आधुनिक तकनीकों संसाधनों के जरिए रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रभावशाली रूप में

प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य मनोरंजन के साथ भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े मयार्द, त्याग, सत्य और कर्तव्य जैसे मूल्यों का प्रसार करना भी है।

63 फिल्मी कलाकारों से सजेगी दिल्ली की रामलीला, 10 से 20 अक्टूबर तक होगा आयोजन- विश्व की सबसे बड़ी रामलीला के रूप में चर्चित अयोध्या की रामलीला का आयोजन 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में किया जाएगा। इसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, रजा मुराद, बिंदु दारा सिंह, मालिनी अवस्थी और मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 काजिया



लिज मेजो समेत 63 फिल्मी कलाकार विभिन्न किरदारों में नजर आएंगे। मेले का आयोजन दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक होगा, जबकि रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा।

19 अक्टूबर को सांसद रवि किशन निभाएंगे श्रीराम की भूमिका- रामलीला में फिल्म और मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियां प्रमुख पात्रों के रूप में नजर आएंगी। आयोजकों के मुताबिक, 19 अक्टूबर को सांसद रवि किशन भगवान श्रीराम की भूमिका निभाएंगे, जबकि अभिनेता अरुण बख्शी रावण का किरदार अदा करेंगे। दोनों कलाकारों की सहभागिता कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगी। संवाद, अभिनय और मंचीय प्रभावों के जरिए रामायण के प्रसंगों

को नए अंदाज में प्रस्तुत करने की तैयारी है, जिससे विभिन्न आयु वर्ग के दर्शक भारतीय परंपराओं से जुड़ सकें।

40 भाषाओं में प्रसारण, 60 देशों तक पहुंचेगा रामकथा का संदेश- आयोजकों के मुताबिक, रामलीला का प्रसारण 80 से अधिक उपग्रह चैनलों के माध्यम से 40 भाषाओं में किया जाएगा। इसके जरिए भगवान श्रीराम के आदर्शों और रामर्भक्ति का संदेश 60 देशों तक पहुंचाने की योजना है। इस बहुभाषी प्रसारण से विदेशों में रहने वाले भारतीयों सहित विभिन्न देशों के दर्शकों को अपनी भाषा में रामलीला देखने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक विरासत और रामायण की शिक्षाओं को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम- रामलीला के आठवें संस्करण में 120 फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन, आकर्षक मंच सज्जा और कलाकारों के अभिनय के जरिए रामायण के प्रसंगों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। पारंपरिक कथा शैली के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आयोजन को खास बना रहा है। बाल कलाकारों की भागीदारी, लोकप्रिय फिल्मी कलाकारों की भूमिकाएं और बहुभाषी प्रसारण इस संस्करण को प्रमुख विशेषताएं हैं। आयोजन के जरिए रामायण की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने और प्रभु श्रीराम के आदर्शों को देश-दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कभी नारी सुरक्षा के सवालों से घिरा यूपी अब बना सामर्थ्य की नई पहचान: सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर किया पोस्ट- मां ब्रह्मचारिणी के तप और संकल्प से सिद्धि का मंत्र सिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी किए जा सकते हैं सिद्ध

- सुरक्षा से सशक्तीकरण की यात्रा सशक्त नारी, समृद्ध-उत्तर प्रदेश के संकल्प को कर रही साकार: मुख्यमंत्री
- 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश महिला पुलिस कार्यबल 10,000 से बढ़कर 44,000 से अधिक हुआ: सीएम योगी

समाचार सेन्टर संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्रि की द्वितीया पर मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से इसके महत्व पर चर्चा की। कहा कि मां ब्रह्मचारिणी के तप और संकल्प से सिद्धि का मंत्र हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी सिद्ध किए जा सकते हैं।

सीएम ने 2017 से पहले और बाद

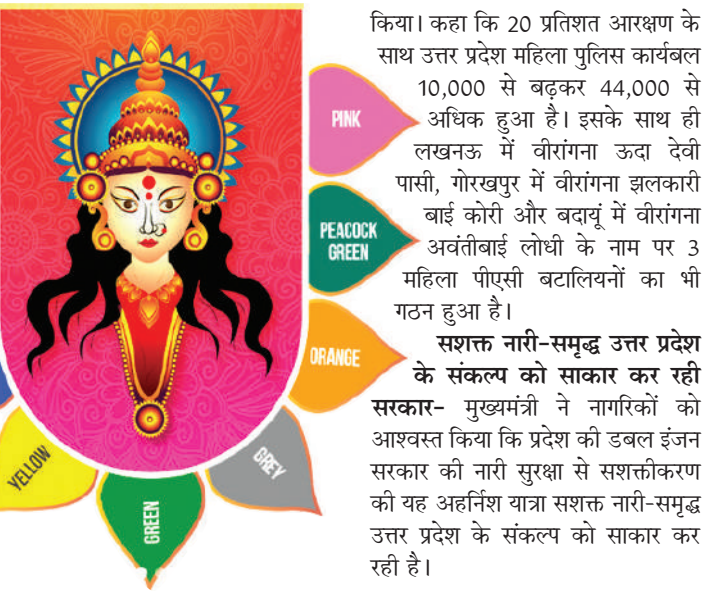
के यूपी की दिखाई तस्वीर- मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर 2017 से पहले और इसके बाद के उत्तर प्रदेश की तुलना की। कहा कि वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर सवालों से घिरा रहने वाला उत्तर प्रदेश आज नारी सुरक्षा और सामर्थ्य की नई पहचान बना है। विगत 9.5 वर्षों में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, तकनीक आधारित निगरानी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जन-जागरूकता



अभियानों ने प्रदेश में महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई है।

महिला सुरक्षा तंत्र को किया सुदृढ़- सीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति के पांच चरणों, सेफ सिटी परियोजना, मिशन शक्ति केंद्रों और महिला बीट पुलिसिंग जैसी पहलों ने महिला सुरक्षा तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।

यूपी पुलिस में 44,000 से अधिक हुआ महिला कार्यबल- मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्यबल में महिलाओं के योगदान का भी जिक्र



किया। कहा कि 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश महिला पुलिस कार्यबल 10,000 से बढ़कर 44,000 से अधिक हुआ है। इसके साथ ही लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पार्स, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर 3 महिला पीएसई बटालियनों का भी गठन हुआ है।

सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार कर रही सरकार- मुख्यमंत्री ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की नारी सुरक्षा से सशक्तीकरण की यह अहर्निश यात्रा सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार कर रही है।

कैंसर इलाज में सहत

सही मायने में इसे एक अमानवीय कृत्य ही कहा जाएगा कि कैंसर जैसे घातक रोग से जूझ रहे मरीजों से दवाओं के मनमाने दाम वसूले जाएं। इस जानलेवा रोग से जूझ रहे मरीजों को यूँ तो उपचार की अन्य मर्दों में भी काफी खर्च करना पड़ता है, लेकिन दवाओं की अधिक कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाना किसी हद तक राहतकारी साबित हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने नॉन-शेड्यूलड एंटी-कैंसर दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन को तीस फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। निस्संदेह, यह कदम उस हेल्थकेयर क्षेत्र में एक स्वागत योग्य पहल है, जहां मरीजों को अधिक पैसा चुकाने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल, कैंसर का त्रास झेल रहे व्यक्ति व उसके परिवार पर इस रोग का उपचार आर्थिक रूप से भारी बोझ डालता है। ऐसे में कैंसर रोग में काम आने वाले दवाइयों की कीमत में कमी लाने का प्रयास समय की जरूरत भी है। सरकार का अनुमान है कि दवाइयों की कीमतों में नये सिरे से नियमन के जरिये मरीजों को हर साल 2,500 करोड़ रुपये तक की बचत होगी। इस बाबत दावा किया जा रहा है कि कुछ दवाइयों की कीमतों में सत्त फीसदी तक की कमी आ सकती है। हालांकि, मरीजों को लाभ के आंकड़े अनुमानित हैं और इनकी हकीकत प्रावधानों के लागू होने पर ही स्पष्ट हो पायेगी। वास्तव में सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दशायीं जा रही राहत वास्तव में मरीजों तक भी पहुंचे। समय रहते अधिकारियों को तुरंत उन दवाओं की जानकारी मरीजों व तिमारदारों को देनी चाहिए, जिन पर वह कटौती लागू की गई है। साथ ही दर्ज की गई कीमतों में बदलाव को भी स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर नजर रखी जानी चाहिए। दूसरी ओर ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर जुमाना लगाया जाना चाहिए। सरकार को यह भरोसा भी कायम करना होगा कि नई कीमत नियमन के लागू होने के बाद दवा कंपनियां सप्लाई यथावत बनाये रखेंगी। सही मायने में कीमतों में आई असली कमी- मरीजों की बचत और दवाइयों की उपलब्धता की समय-समय पर जानकारी देने से ही सुनिश्चित हो सकेगी। तभी पता चलेगा कि यह कदम वास्तव में कितना कारगर है। दरअसल, सरकार द्वारा कैंसर के मरीजों को राहत देने का यह प्रयास नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के 2019 के उस फैसले को ही आगे बढ़ाता है, जिसमें 42 नॉन-शेड्यूलड कैंसर-रोगी दवाओं को शामिल किया गया था। दावा किया जाता रहा है कि उस पहल के उपरांत दवाइयों के 526 ब्रांड्स में वार्षिक रूप से 984 करोड़ रुपये की बचत मरीजों को हुई थी। अतः पिछला अनुभव बताता है कि ट्रेड मार्जिन को रेगुलेट करने से पूरी मार्केट में एक जैसी कीमतें लागू किए बिना भी मरीजों को वैसाविक लाभ जमीनी स्तर पर मिल सकता है। वास्तव में कैंसर के मरीजों को राहत देने के उपायों के क्रम में और अधिक दवाइयों को इस राहत के दायरे में लाना होगा। जिसमें विदेशों से आयातित और पेटेंटड दवाइयां भी शामिल हैं। तभी कैंसर रोगियों को वास्तव में अधिक राहत मिल सकेगी क्योंकि अभी भी उन्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। वैसे हकीकत में देखा जाए तो दवाइयों के मूल्य की सीमा तय करने के बाद भी कैंसर के मही इलाज का कारगर व्यापक समायान संभव नहीं है। दरअसल, मरीजों के सामने जांच, सर्जरी, रेडिएशन, अस्पतालों में भर्ती होने और इलाज के बाद की देखभाल के लिये भारी-भरकम बिल चुकाने की मजबूरी होती है। राहत के लिये अस्पतालों के जरिये बेची जाने वाली चिकित्सा सामग्री और दवाइयों की ज्यादा कीमतों की भी जांच होगी चाहिए। पिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने भी इस बात को लेकर चिंता जतायी थी कि अस्पतालों में दवाइयों और चिकित्सा में सहायक उपकरणों के दाम मनमाने तरीके से वसूल जाते हैं। निश्चित रूप से देश में सुप्रीम कोर्ट की चिंता के अनुरूप चिकित्सा तंत्र में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है।

तय करना होगा कि मतदाता सरकार चुनेगा या सत्ता मतदाता को चुनेगी?

तानाशाही हमेशा गोलियाँ और टैंक लेकर नहीं आती... कभी-कभी अटपटे फॉर्म और चुनावी धाँधली के रास्ते भी आती है। एसआईआर को लेकर सवाल अब लगातार गहराते जा रहे हैं। इसके जरिए इस आधे-अधूरे लोकतंत्र को भी खत्म करने की साजिशों की बू आ रही है।

निर्वाचन आयोग के ही दो चुनाव आयुक्तों-सुखबीर सिंह संघू और विवेक जोशी-ने चुनाव प्रक्रिया में किए जा रहे बदलावों को लेकर पिछले 10 महीनों में कम-से-कम 14 बार आयोग के भीतर आपत्तियाँ दर्ज कीं। फॉर्म 6 को लेकर दोनों ने आपत्ति की। जोशी ने कहा कि निर्धारित फॉर्म 6 को नियमों में बदलाव किए बिना बदला नहीं जा सकता। बाद में संघू ने इस बदलाव को अनधिकृत/अवैध बताते हुए इसे तत्काल हटाने की बात कही। लेकिन फिर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सारी आपत्तियों को अनदेखा कर अपनी मनमर्जी चलाये जा रहे थे, आखिर क्यों? और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि संशोधित फॉर्म 6 को उसकी मंजूरी नहीं मिली थी, जबकि नियमों के मुताबिक इसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ही संशोधित किया जा सकता है।

अब सवाल है-इसे किसने बदला, किसकी मंजूरी से बदला और क्यों बदला?

तो सवाल सिर्फ एक फॉर्म 6 का नहीं है।

सवाल लोकतंत्र के उस दरवाजे का है, जिससे होकर नागरिक सरकार चुनता है। क्योंकि तानाशाही हमेशा टैंक, बंदूक और गोलियों के साथ नहीं आती।

कभी वह एक साधारण-से फॉर्म के रास्ते आ सकती है, कभी मतदाता सूची के रास्ते-असल नाम हटाकर, नकली नाम जोड़कर,



कभी ईवीएम की गड़बड़ियों के रास्ते, कभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आयकर विभाग (आईटी) जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के रास्ते, कभी विधायकों-सांसदों की खरीद-फरोख्त के रास्ते, और कभी अदालतों के जनविरोधी फैसलों के रास्ते।

सबसे बड़ा खतरा तब है- जब जनता सरकार चुनने जाए, लेकिन उससे पहले यह तय किया जाने लगे कि कौन जनता की ओर से वोट देने का अधिकार रखता है और कौन नहीं।

फिर सवाल सीधा है- लोकतंत्र में मतदाता सरकार

चुनता है, या किसी खास राजनीतिक पार्टी और उसकी चाटुकार संस्थाएँ मिलकर अब मतदाता चुनने लगी हैं?

क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है-निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र मतदाता, बहुसंख्यक जनता के हितों के अनुरूप शासन-तंत्र और सत्ता की जवाबदेही। क्या एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र का गला नहीं घोंटा जा रहा है?

क्या संस्थाओं का दुरुपयोग कर-के तानाशाही कायम नहीं की जा रही है? क्या इन सारी धाँधलियों के बढ़ने

के साथ-साथ पूँजीपतियों और भ्रष्टाचारियों को देश को लूटने-खसोटने की छूट भी बढ़ती नहीं जा रही है?

क्या इसके विरोध में उठने वाली आवाजों का दमन करना और महिलाओं के साथ बदतमीजी करना सत्ता की गुंडागर्दी नहीं है? अब सिर्फ सवाल नहीं- जवाबदेही चाहिए।

सबसे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो मतदाताओं का विश्वास खो चुके हैं, को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

एसआईआर और फॉर्म 6 में हुए बदलावों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और

समयबद्ध जाँच हो। स्पष्ट किया जाए-बदलाव किसने किया, किसकी मंजूरी से किया और किसके निर्देश या प्रभाव में किया।

जिन राज्यों में एसआईआर के बाद चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पूरी चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की स्वतंत्र जाँच हो। यदि यह साबित होता है कि एसआईआर के कारण वैध मतदाता मतदान से वंचित हुए, या फर्जी मतदाता जोड़े गए, या चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई, तो संबंधित चुनाव को रद्द कर पुनर्निर्वाचन कराया जाए।

एसआईआर में हटाए गए प्रत्येक मतदाता के मामले की स्वतंत्र समीक्षा हो और गलत तरीके से

हटाए गए नाम तत्काल बहाल किए जाएँ।

निर्वाचन आयोग और प्रशासन के उन अधिकारियों की उच्चस्तरीय जाँच हो, जिन्होंने इस प्रक्रिया में निर्णय लिए। साथ ही, जिन राजनीतिक दलों, नेताओं या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों पर अनुचित दबाव या हस्तक्षेप के आरोप हैं, उनकी भी उच्चस्तरीय और समयबद्ध जाँच हो।

दोष सिद्ध होने पर सभी दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाए। मामलों का समयबद्ध न्यायिक निपटारा हो, ताकि लोकतंत्र से जुड़े अपराध और अनियमितताएँ वर्षों तक फाइलों में दबी न रहें।

क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसने फॉर्म 6 बदला।

सवाल यह है- क्या किसी ने मतदाता के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया? और अगर किया, तो जवाबदेह कौन है?

लोकतंत्र में मतदाता सरकार चुनता है- सत्ता मतदाता नहीं चुनती।



हाल के वर्षों में सारे आंदोलनों में अराजक हिंसा के इश्य हमने देखे हैं। कृषि कानूनों को लेकर धरना और आंदोलन इतना अराजक व हिंसक हुआ कि प्रदर्शनकारी लाल किले पर चढ़ गए, तिरंगा उतारकर दूसरा झंडा लगा दिया। हालिया जंतर-मंतर आंदोलन में भी पुलिस की गाड़ियों को उलटाना, तोड़ना,घेरकर पीटना और पत्थरबाजी भी प्रदर्शन के भाग थे। जिसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारियों को पीटते नजर आये जिनका अब तक खुलासा न होना भी उगता के कारण बनता जा रहा है अग्निवीर योजना के विरुद्ध हुए आंदोलन में भी जबर्दस्त हिंसा हुई। मसलन, बिहार में कुछ नेताओं के घरों पर

हमले हुए। ट्रेन, बस और थाने तक जले। क्या आंदोलनों का यह चरित्र डराना नहीं है? देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों में भी दूर-दष्टि विवेक और देश के भविष्य को ध्यान में रखकर सोचने वालों की संख्या बेहद कम है। जो हैं भी वे अक्सर पार्टी में प्रभावी भूमिका में नहीं हैं। इसलिए, पार्टियाँ या तो मौन रहती हैं या सिर्फ दमन और अत्याचार जैसे मुहावरों का उपयोग कर छुट्टी पा लेती हैं। वास्तव में हम एक ऐसे डरावने दौर में हैं, जहाँ से जितना 'आगे बढ़ेंगे,उतना अनर्थ होगा। लोकतंत्र में किसी को भी धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने का अधिकार है। सत्ता अथवा किसी स्तर पर कोई फैसला या कार्रवाई जनविरोधी या अन्यायपूर्ण है,तो उसके प्रतिकार का रास्ता हमें अतीत से अहिंसक आंदोलनों के रूप में मिला है। लेकिन, इनकी मर्यादा और गरिमा रही है। आजकल सभी महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण (जेपी)



का नाम लेते हैं। तिरंगा और संविधान लहराते हैं, पर क्या गांधीजी की भाषा का मर्म आत्मसात करते हैं? जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध छत्र आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व लिया,तो छत्र नेताओं से लिखवाया कि वे हिंसा न

करने के साथ अभद्र और उग्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। गांधीजी ने चोरी-चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था जयप्रकाश जी ने नारा भी दिया था- 'चाहे चले लाठी-गोलियाँ,हाथ हमारा नहीं उठेगा। इन महामुरुषों के

लिए साध्य और साधन दोनों की पवित्रता सर्वोच्च मानने रखती थी। आज तो भाषा में हिंसा, उग्रता और अभद्रता स्पष्ट दिखती है। जैसे नारे लगते हैं या पोस्टर दिखाए जाते हैं, वैसी भाषा व उग्रता अकल्पनीय है। वास्तविक आंदोलनकारी-

सत्याग्रही, अपनी मांग को लेकर धरना देते हैं,प्रदर्शन करते हैं, पर कभी अराजकता की सीमा तक नहीं पहुंचते। अब तो ऐसा लगता है, मानो आंदोलन नहीं, युद्ध के मोर्चों में उतरे हैं। जैसे नारे लगते है या पोस्टर दिखाए जाते हैं, वैसी भाषा व उग्रता अकल्पनीय है।

प्रश्न है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई क्यों? जब भी कोई आंदोलन हिंसक हो,उसमें अव्यक्त तत्वों की भूमिका की पुष्टि हो जाए,तो प्रशासन का दायित्व है कि बिना देर किए उसे कठोरता से नियंत्रित करें। नहीं तो अराजक तत्व उसे उग्रवादी और हिंसक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग

ही हम संसद तक चले जाते और अतिवादी मानसिकता सामान्य मानी जाने लगी है, जिससे निहित स्वार्थी तत्वों को मौका मिल जाता है। एक विचित्र पैटर्न देखने में आता है-पहले धरना शुरू होता है, फिर सड़क घेर ली जाती है और कुछ स्थायी निर्माण भी हो जाते हैं। अंततः दंगे की स्थिति बन जाती है। ऐसे में,शेप नागरिकों के अधिकारों का क्या? देश की राजधानी की नाकेबंदी और जनता में दहशत का माहौल बने,इससे पहले ही प्रशासनिक प्रयास या सरकार दो कदम आगे आकर इसके निराकरण के लिए उपाय या रास्ता अखिरवार क्यों नहीं किये जाते? ताकि आन्दोलन की नौबत ही न आने पाये।

एक आंदोलन के वक्त तो पूरी दिल्ली हलकान हो गई थी,औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कच्चे माल व सामग्रियों को आपूर्ति का संकट पैदा हो गया था, लोग त्रिह-

त्राहित करते रहे, पर कार्रवाई नहीं हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी को केंद्र बनाकर अमेरिका से अभिजित दिफेंके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया, तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि जंतर-मंतर पर पहले से धरने की अनुमति भी नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने त्वरित अनुमति दी। आगे चलकर प्रशासनिक हल्केपन से अराजक, अव्यक्त तत्वों को भी इसकी आड़ में मौका मिल गया आखिरी लंबे समय से निष्क्रिय छटपटाते लोगों के लिए भी इस बैनर के नाम पर एक माध्यम मिल गया है। कानून व्यवस्था और देश में स्थिरता शांति व प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। समग्र रूप से विचार कर इस प्रवृति को नहीं रोका गया,तो अराजक तत्वों का आंदोलनों में प्रवेश सामान्य हो जाएगा और फिर हिंसा का एक सीमा के बाद रोकना निहायत मुश्किल होगा।

- लेखक सामाजिक विचारक हैं।

अभिनय से बड़ी उनकी इंसानियत की विरासत

सोशल मीडिया पर कर्मिडी रील देखते हुए अंत में एक चेहरा सामने आता है। जोर-जोर से हँसता हुआ, आंखों में शरारत और चेहरे पर वही बेतकल्लुफी, जिसे देखते ही वेलकम के उदय शेट्टी की याद आ जाती है। यह चेहरा नाना पाटेकर का है। कभी इस चेहरे पर दर्शक हँसे थे, कभी इसकी आंखों में गुस्सा देखकर सहमे थे और कभी इसकी आवाज में छिपी पीड़ा ने उन्हें भीतर तक छुआ था। अब यह चेहरा असल दुनिया से विदा हो गया। नाना ने अपने पीछे अभिनय से कहीं बड़ी इंसानियत की विरासत छोड़ी है।

नाना पाटेकर दुनिया से चले गए, लेकिन उनका चेहरा शायद ही कभी हमारी स्मृतियों से विदा होगा। फिल्मों में वे जितनी बार दिखेंगे, उतनी ही बार उनकी आवाज कानों में गुंजेगी और उनके किरदार सामने आकर खड़े होंगे। मगर नाना को सिर्फ अभिनेता के रूप में याद करना उनके व्यक्तित्व से न्याय नहीं होगा। उन्होंने पर्दे पर जितना अभिनय किया, उससे कहीं ज्यादा गहरी भूमिका उन्होंने जिंदगी में निभाई। पर्दे पर वे कठोर थे, आक्रामक थे, व्यवस्था को चुनौती देते थे, कभी अपराधी बने, कभी सैनिक व कभी विद्रोही नायक। लेकिन केमरा बंद होने के बाद वही आदमी उन लोगों के बीच खड़ा दिखाई देता, जिनकी पीड़ा

सुनने वाला भी कोई नहीं था। नाना पाटेकर को याद करते हुए सबसे पहले उनकी आवाज सुनाई देती है-भारी, खुदगुदी और सीधे दिल में उतर जाने वाली। फिर उनका चेहरा सामने आता है। कभी गुस्से से तना हुआ, कभी व्यवस्था से लड़ता, कभी किसी को चुनौती देता और कभी अचानक खिलखिलाकर हँसता हुआ। हिंदी और मराठी सिनेमा में उन्होंने ऐसे किरदारों को जन्म दिया, जिन्हें केवल अभिनय से नहीं, अपने पूरे व्यक्तित्व से जिया। परिदा का अन्ना हो, प्रहार का कठोर सैनिक, क्रांतिवीर का प्रताप हो या तिरंगा का तेवर-नाना ने हर किरदार को अपनी आवाज, आंखों और देहभाषा से ऐसा रूप दिया कि वह चरित्र अभिनेता से बड़ा होकर सिनेमा की स्मृति का हिस्सा बन गया। फिर वही नाना वेलकम में उदय शेट्टी बनकर सामने आए तो उनकी अभिनय क्षमता का दूसरा सिरा भी दिखाई दिया। जिस अभिनेता को देखकर दर्शक परिदा और क्रांतिवीर में सहम दर्शते थे, वही वेलकम में अपनी अजीबो-गरीब हंसी, अंदाज और संवादों से लोगों को हँसाता रहा।

उनकी खासियत थी कि वे किसी एक खांचे में फिट होने वाले अभिनेता नहीं थे। उनके भीतर गुस्सा भी था, करुणा



भी; कठोरता भी थी और हास्य भी। नाना पाटेकर का फिल्मी सफर 1978 की गमन से शुरू हुआ। अंकुश ने उन्हें पहचान दी और परिदा ने उनके अभिनय को नई उंचाई तक पहुंचाया। इसके बाद प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी, अनिसाक्षी, अब तक छपन, नटसम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय के विविध रंग सामने रखे। उन्होंने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से लेकर 2013 में पद्मश्री सम्मान तक हासिल किया। लेकिन पुरस्कारों की लंबी सूची उस नाना को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकती, जिसे उनके चाहने वाले एक बेहद सादा और संवेदनशील इंसान के रूप में याद करते हैं। नाना एक

संवेदनशील इंसान थे। महाराष्ट्र की किसानों की त्रासदी ने उन्हें भीतर तक झकझोरा। विदर्भ और मराठवाड़ा के सूखे इलाकों में जब किसानों की आत्महत्याओं की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, तब उन्होंने केवल दुःख जताने तक खुद को सीमित नहीं रखा। वे गांवों में गए, किसानों से मिले, उनके परिवारों के बीच बैठे और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। किसान परिवारों की सहायता के लिए काम शुरू किया, जो आगे चलकर नाम फाउंडेशन के रूप में सामने आया। यह नाना की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा अध्याय था। जिस आदमी को सिनेमा ने करोड़ों लोगों की पहचान दी, उसने उस पहचान को अपने लिए नहीं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया।

यहाँ नाना पाटेकर अपने फिल्मी किरदारों से कहीं बड़े दिखाई देते हैं। पर्दे पर उन्होंने ऐसे किरदार निभाए, जो अपने गुस्से और तेवर से व्यवस्था को चुनौती देते थे। असल जिंदगी में उन्होंने उन लोगों का साथ देने की कोशिश की, जो व्यवस्था की सबसे कमजोर सीढ़ी पर खड़े थे। शायद इसलिए उनकी सामाजिक भूमिका उनके अभिनय से अलग नहीं थी। दोनों के पीछे एक ही चीज काम करती थी-अन्याय और पीड़ा को देखकर भीतर से बेचैन हो जाना। नाना

को दिखावे से हमेशा दूरी रही। उनका रहन-सहन सादा रहा। बातचीत में भी बनावटीपन नहीं था। यही वजह थी कि उन्हें देखकर लगता था कि यह व्यक्ति पर्दे पर जितना बड़ा अभिनेता है, निजी जिंदगी में उतना ही सहज इंसान है। नाना पाटेकर का जाना सिनेमा के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान है, लेकिन शायद उससे भी बड़ी क्षति उस दुनिया की हुई है, जहाँ नेकी को प्रचार की जरूरत नहीं होती। वे अपनी फिल्मों में जीवित रहेंगे, उनके संवाद फिर सुनाई देंगे, वेलकम का उदय शेट्टी देखकर लोग फिर हँसेंगे और क्रांतिवीर या परिदा में वही पुराना गुस्सा फिर दिखाई देगा। मगर अब इन दृश्यों के पीछे खड़ा असली नाना दिखाई नहीं देगा। वह आदमी, जो पर्दे पर खूंखार हो सकता था, लेकिन जिंदगी में किसी किसान के आंसू देखकर पिघल जाता था। वह अभिनेता, जिसने लाखों दर्शकों को डराया भी, हँसाया भी व रूलाया भी, लेकिन असल जिंदगी में दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता रहा। शाकद यही नाना पाटेकर की सबसे बड़ी विरासत है। सिनेमा का पर्दा उनके बिना जरूर सूना होगा, लेकिन नेकी की दुनिया में जो जगह उन्होंने बनाई, उसे भर पाना आसान नहीं होगा।

- हेमंत पाल

स्वच्छता पखवाड़ा 2026 ट्रैक साइड क्लीनिंग ड्राइव

समाचार सेन्टर संवाददाता

लखनऊ। स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल में मण्डल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर/ईएनएचएम महेन्द्र सिंह



क्लीनिंग व प्रेशर वाशिंग की गई तथा ट्रैक साइड की सफाई करायी गयी।

मैलानी जं० स्टेशन पर सकुलेंटिंग एरिया, वाटर बूथ, कैटोन, पैनल रूम एवं प्लेटफार्म, ट्रैक की सघन सफाई की गई। लखीमपुर, गोरखपुर जं. व बस्ती

आदि स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं एवं ट्रैक साइड की गहन सफाई की गई। इसके साथ ही बस्ती स्टेशन पर रनिंग लाइनों के किनारे फैले कूड़े की सफाई कर कूड़ेदान में एकत्रित कचरे का पृथक्करण कर निस्तारण कराया गया। डॉ. संजय तिवारी, अपर मुख्य

चिकित्सा अधीक्षक, ऐशबाग के निर्देशन में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अभिजीत गुप्ता द्वारा ऐशबाग लोको कालोनी में घर-घर से कूड़ा एकत्र कर SWM Rule 2026 के अनुसार पृथक्करण कर नगर निगम के माध्यम से निस्तारण किया गया एवं लोगों को जागरूक किया गया।

जेपी की आड़ में अपने भ्रष्टाचार व परिवारवाद पर पर्दा डालते हैं अखिलेश : ब्रजेश पाठक का हमला

समाचार सेन्टर संवाददाता



लखनऊ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके योगदान और स्मृतियों को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नमन किया है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। पाठक ने कहा कि जयप्रकाश नारायण, लोहिया, नरेंद्र देव, ऐसे महापुरुष हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कथनों में सिर्फ उद्धृत ही नहीं करते हैं बल्कि उनके बताए गए मार्ग पर भी चलने का काम करते हैं। पाठक ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने योगी के नेतृत्व में JPNIC को लीज पर देकर लोकनायक की स्मृतियों को संजोते हुए चलाने का काम किया है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दवा

कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार सभी महापुरुषों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण, लोहिया, नरेंद्र देव, ऐसे महापुरुष हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कथनों में सिर्फ उद्धृत ही नहीं करते हैं बल्कि उनके बताए गए मार्ग पर भी चलने का काम करते हैं। पाठक ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने योगी के नेतृत्व में JPNIC को लीज पर देकर लोकनायक की स्मृतियों को संजोते हुए चलाने का काम किया है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दवा

तो यह भी किया जा रहा है कि उस समय की तत्कालीन सरकार के मुखिया ने अपने परिवार को ही JPNIC को चलाने का जिम्मा दे दिया था। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि JPNIC में फाइव स्टार सुविधाओं के साथ-साथ स्विमिंग पूल भी है और वो किस राजनीतिक समाजवादी नेता के उपयोग में आएगा, प्रदेश की जनता इसे अच्छी तरह समझती है। ब्रजेश पाठक ने सवाल करते हुए कहा कि सपा प्रमुख को बताना चाहिए कि प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से कमाया हुआ धन क्या सुख-सुविधा के लिए खर्च किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जीवन भर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे और कभी भी अपने लिए उन्होंने पूंजी एकत्र नहीं की।

हाई ब्लड प्रेशर: सिर्फ नंबर नहीं, जड़ को समझिए



डा. संजीव अग्रवाल

हार्ट अटैक, लकवा (स्ट्रोक) और किडनी फेल होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है हाई ब्लड प्रेशर, और इसका इलाज मुमकिन है। मुश्किल यह है कि ज्यादातर मरीजों को कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती। दुनिया में करीब 130 करोड़ लोगों को हाई बीपी है। इनमें से लगभग आधों को पता ही नहीं, और सिर्फ पाँच में से एक का बीपी कंट्रोल में है।

आम तौर पर होता यह है कि बीपी नापा, बीमारी का नाम बताया और गोली लिख दी। यह तरीका जान बचाता है और इस लेख में उसके खिलाफ कुछ उपाय कहा गया है। लेकिन बढ़ा हुआ बीपी शरीर का एक संदेश भी है। नमक, शक्कर, तनाव या नींद को संभालने में शरीर के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। यह लेख उसी जड़ को ढूँढ़ने की बात करता है। जड़ पकड़ में आ जाए और ठीक हो जाए, तो बीमारी से बचाव मुमकिन है, इलाज बेहतर काम करता है और कई लोगों को कम दवा की जरूरत पड़ती है।

हाई ब्लड प्रेशर क्या है?— खून जब नसों (धमनियों) में बहता है तो उनकी दीवारों पर दबाव डालता है। इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे दो नंबरों में लिखा जाता है। ऊपर वाला नंबर वह दबाव है जब दिल धड़ककर खून को आगे धकेलता है। नीचे वाला नंबर वह दबाव है जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम करता है। जब यह दबाव दिन-ब-दिन लगातार बढ़ा रहता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि नुकसान होता है। इससे दिल, नसों, दिमाग, किडनी और आँखों पर हर वक्रत जोर पड़ता रहता है। ये नंबर डॉक्टर के क्लिनिक में नापे गए बीपी के हैं। घर पर बीपी थोड़ा कम आता है, इसलिए घर का 135/85 क्लिनिक के 140/90 के बराबर माना जाता है। कुछ अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन अब 130/80 को भी ज्यादा मासती हैं, क्योंकि नुकसान जल्दी शुरू हो जाता है।

एक बार नापने से बीमारी तय नहीं होती। सही तरीका यह है?— पाँच मिनट चुपचात कुर्सी पर बैठें, पीट टिकी हो और बाँह दिल की ऊँचाई पर हो, बाँह पर बाँधने वाली अच्छी मशीन इस्तेमाल करें, और पढ़ा सही नाप का हो, नापने से 30 मिनट पहले चाय, कॉफी, तंबाकू और कसरत से बचें, सुबह और शाम दो-दो बार नापें, एक हफ्ते तक, और औसत अपने डॉक्टर को दिखाएँ।

शुरूआती लक्षण- सबसे आम शुरूआती लक्षण है: कोई लक्षण नहीं। कुछ लोगों को सुबह सिर के पिछले हिस्से में दर्द, चक्कर, थकान, घबराहट या धड़कन तेज लगाना, नकसीर और धुँधला दिखना महसूस होता है। लेकिन इन पर धोखा नहीं किया जा सकता। ये दूसरी बीमारियों में भी होते हैं, और बीपी में अक्सर तब आते हैं जब वह बहुत बढ़ चुका होता है। लक्षणों का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है। बीपी जानने का एक ही तरीका है: उसे नापना।

क्या बिना किसी लक्षण के बीपी खतरनाक हद तक बढ़ सकता है?— जी हाँ, और इसीलिए इसे साइलेंट किलर

यानी खामोश क़ातिल कहा जाता है। कई लोग बिल्कुल ठीक महसूस करते हुए क्लिनिक आते हैं और उनका बीपी 180/110 या उससे भी ज्यादा निकलता है। बीपी सालों में धीरे-धीरे बढ़ता है, शरीर उसका आदी हो जाता है और कुछ गलत महसूस नहीं होता। लेकिन अंदर नुकसान चलता रहता है। नसें सख्त और मोटी हो जाती हैं। दिल की मांसपेशी पहले मोटी होती है, फिर कमजोर। किडनी से पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है। दिमाग और आँखों की बारीक नसें सिकुड़ने लगती हैं। बहुत से लोगों में पहला लक्षण ही लकवा, हार्ट अटैक या किडनी की खराब रिपोर्ट होता है। 18 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार बीपी जरूर नपवाना चाहिए। अगर परिवार में किसी को बीपी है, वजन ज्यादा है, शुगर है या किडनी की तकलीफ है, तो और जल्दी-जल्दी नपवाएँ।

कम उम्र में बीपी क्यों बढ़ रहा है?— बीस-तीस साल की उम्र में हाई बीपी अब कोई अनोखी बात नहीं रही। इसकी ज्यादातर वजहें हमारे आज के रहन-सहन में छिपी हैं, और अक्सर कई वजहें एक साथ होती हैं।

बढ़ा हुआ वजन, खासकर पेट की चर्बी। पेट की चर्बी शरीर में नमक और पानी रोकती है और नसों को सख्त बनाती है। नौजवानों में यह सबसे बड़ी वजह है। पैकेट और बाहर का खाना। नमकीन, चिप्स, होटल का खाना और मोटे टंडे पेय में नमक और चीनी बहुत होती है, और ताजा फल-सब्जी लगभग नहीं। दिन भर बैठे रहना। घंटों कुर्सी और मोबाइल-स्क्रीन, और कसरत के नाम पर कुछ नहीं। कम और टूटी-फूटी नींद। देर रात तक जागना, शिफ्ट की नौकरी, और जोर के खराटे जिनमें साँस बीच-बीच में रुकती है। लगातार तनाव। काम और पैसे की चिंता से तनाव के हार्मोन बढ़े रहते हैं। शराब, तंबाकू और उत्तेजक चीजें। इसमें एनर्जी ड्रिंक और बहुत ज्यादा चाय-कॉफी भी शामिल हैं। परिवार में बीपी होना। माँ-बाप से झुकाव मिलता है, पर बीमारी को अक्सर रहन-सहन ही जगाता है। कुछ दवाएँ और सर्प्लीमेंट। रोज ली जाने वाली दर्द की गोलीयाँ, गर्भनिरोधक गोलीयाँ, स्टेरॉयड, बंद नाक की दवाएँ, बाँड़ी बनाने वाले स्टेरॉयड, जिम के कुछ प्री-वर्कआउट पाउडर और मुलेटी।

जब कोई खास बीमारी वजह हो- ज्यादातर लोगों में कोई एक बीमारी नहीं मिलती। लेकिन कम उम्र में छिपी हुई वजह मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जिसे 40 साल से पहले बीपी निकले, उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। आम छिपी वजहें हैं: किडनी की तकलीफ, थायरॉइड या दूसरी हार्मोन ग्रंथियों की गड़बड़ी, किसी नस का सिकुड़ना, और नींद में बार-बार साँस रुकना। ऐसी वजह का मिलना बड़ी बात है। कई बार इससे जिंदगी भर की दवा की जगह बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है।

नमक, तनाव और रहन-सहन का कितना असर पड़ता है?— बहुत ज्यादा। रहन-सहन का हर बदलाव, अगर ठीक से किया जाए, तो बीपी को लगभग एक गोली जितना घटा देता है। और ये असर आपस में जुड़ते जाते हैं। ये हाई बीपी के मरीजों पर हुए अध्ययनों के मोटे औसत हैं। हर व्यक्ति में असर अलग-अलग होता है।

नमक- विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह है कि दिन भर में 5 ग्राम से कम नमक खाएँ, यानी लगभग एक छोटी चम्मच। भारत में औसतन इससे दुगुना खाया जाता है। ज्यादातर नमक नमकदानी से नहीं आता। वह अचार, पापड़, नमकीन, साँस, ब्रेड, बिस्कुट और



MEGASTAR
REDEFINING HEALTHCARE

होटल के खाने में छिपा होता है। कुछ लोगों पर नमक का असर ज्यादा होता है, खासकर बुजुर्गों, ज्यादा वजन वालों, शुगर और किडनी के मरीजों पर।

पोटेशियम- सिर्फ नमक (सोडियम) कम करना काफी नहीं है, पोटेशियम बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। पुराने जमाने के खाने में पोटेशियम ज्यादा और नमक कम होता था। आज उलटा है। फल, सब्जियाँ, दालें और नारियल पानी यह संतुलन वापस लाते हैं।

तनाव- अचानक आया तनाव बीपी को कुछ मिनटों या घंटों के लिए बढ़ाता है। लंबा चलने वाला तनाव चुपचाप काम करता है: तनाव के हार्मोन बढ़े रहते हैं, नींद बिगड़ती है, खाना-पीना बिगड़ता है, शराब बढ़ती है और कसरत छूट जाती है। अकेला तनाव शायद ही कभी हमेशा का हाई बीपी बनाता है, पर वह बाकी हर वजह को और बढ़ा देता है।

कुल मिलाकर- 50 साल से कम उम्र के लोगों में ज्यादातर हाई

ज्यादा है, कम उम्र में शुरू हुआ है या दवा से काबू में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कुछ और जाँचें भी करवा सकते हैं। जाँच की रिपोर्ट यह बताती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलना है। जो लोग रोज नहीं हैं जिन्हें गोलीयों से ठीक करने के पीछे भागा जाए।

पूरा इलाज: चार बुनियादें- किसी भी कैम्पुल से पहले चार बुनियादें आती हैं: खाना, नींद, चलना-फिरना और शांत मन। सर्प्लीमेंट और दवाएँ इन्हीं के ऊपर बेहतर काम करती हैं।

नसों के लिए सही खाना- बीपी घटाने में जिस खान-पान का सबसे पक्का सबूत है, वह बहुत सीधा-सादा है: खूब सब्जियाँ, फल, दालें, साबुत अनाज, मेवे और कम मलाई वाला दूध-दही, और पैकेट का खाना, चीनी और नमक बहुत कम। डॉक्टर इसे डैश डाइट कहते हैं, यानी हाई बीपी रोकने वाला खान-पान, लेकिन इसके लिए किसी खास चीज की

मरीजों और कुछ दवाएँ लेने वालों के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए पहले डॉक्टर से

पूछें।
नींद की हिफाजत- सोते समय बीपी को 10 से 20 प्रतिशत गिरना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो हार्ट अटैक और लकवे का खतरा बढ़ता है। जो लोग रोज छह घंटे से कम सोते हैं, उनमें हाई बीपी ज्यादा पाया जाता है।

सात से आठ घंटे सोएँ, सोने और उठने का समय रोज एक ही रखें, छुट्टी के दिन भी, कमरा अँधेरा, ठंडा और शांत रखें; सोने से एक घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें, दोपहर के बाद चाय-कॉफी नहीं; राह में भारी खाना और शराब नहीं, सुबह की धूप लें, इससे शरीर की घड़ी ठीक रहती है।

खराटों को हल्के में न लें। जोर के खराटें, नींद में साँस का रुकना, सुबह उठकर थकान लगना और दिन में झपकी आना स्लीप एपनिया की ओर इशारा करते हैं। इस बीमारी में नींद के दौरान साँस बार-बार रुकती है। कई दवाओं के बावजूद बीपी काबू में न आने की यह एक बहुत आम वजह है। नींद की जाँच (स्लीप स्टडी) से यह पक्की होती है, और इलाज से बीपी भी सुधरता है और जिंदगी भी।

रोज चलें-फिरें- हर बार की कसरत के बाद बीपी 24 घंटे तक कम रहता है। महीनों तक करते रहने से नसें लचीली होती हैं और शरीर शक्कर को बेहतर संभालता है।

तेज चाल: हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना। रफ़्तार इतनी हो कि आप बात कर सकें पर गाना न गा सकें।

ताकत की कसरत: हफ्ते में दो बार, वजन, रबर बैंड या अपने शरीर के वजन से।

रुककर करने वाली कसरत: दीवार से पीट टिकाकर कुर्सी की तरह बैठना, या हाथ से स्प्रिंग वाला ग्लिर दबाना, कुछ मिनट, हफ्ते में तीन बार। नए अध्ययनों में इनसे बीपी में अच्छी-खासी कमी देखी गई है।

दिन भर में: हर आधे घंटे बैठने के बाद उठकर कुछ मिनट टहल लें। योग में कसरत, साँस और आराम तीनों हैं, और इससे भी कुछ फायदा देखा गया है। जिनका बीपी 180/110 से ऊपर है, या जिन्हें सीने में दर्द या साँस फूलने की तकलीफ है, वे जोरदार कसरत शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछ लें।

मन को शांत रखें- रोज 10 से 15 मिनट धीमी, गहरी साँस लेने से (एक मिनट में लगभग छह साँस) बीपी कुछ अंक कम होता है। प्राणायाम, ध्यान, पूजा-प्रार्थना, खुली हवा में समय बिताना और परिवार-दोस्तों के साथ बैठना भी इसी तरह काम करते हैं। कभी थोड़ी होती है, पर इनसे नींद सुधरती है और बाकी सारे बदलाव निभाना आसान हो जाता है।

तंबाकू हर रूप में छोड़ना भी इसी में आता है: बाँड़ी, सिगरेट, गुटखा, खेनी, सब। दिल और नसों के लिए इससे बड़ा कोई एक कदम नहीं है।

पोषक तत्व और सर्प्लीमेंट: क्या काम आता है और कितना, सर्प्लीमेंट से बीपी में ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 अंक की ओर कमी आती है। ये चार बुनियादों का साथ देते हैं; उनकी या डॉक्टर की लिखी दवा को जगह नहीं लेते। इन्हें दो हिस्सों में समझिए।

आम कमियों को पूरा करना- इनकी जाँच और पूर्ति हर किसी के लिए फायदेमंद है, बीपी हो या न हो।

मैग्नीशियम- नसों को ढीला रखने में मदद करता है। जिस खाने में हरी सब्जी, मेवे और साबुत अनाज कम हों, उसमें यह कम मिलता है। पेशाब बढ़ाने वाली बीपी की गोलीयाँ इसे और निकाल देती हैं।

विटामिन डी- इसकी कमी बहुत आम है और ज्यादा बीपी से जुड़ी पाई गई है। कमी पूरी करना हड्डियों और मांसपेशियों के लिए अच्छा है, हालाँकि सिर्फ इससे बीपी कम होना साबित नहीं हुआ है।

विटामिन बी12 और फोलेट- नसों और तंत्रिकाओं की सेहत के लिए जरूरी। शाकाहारी लोगों में बी12 की कमी आम है।

ओमेगा-3- जो लोग मछली नहीं खाते, उनमें अक्सर कम होता है। ये मात्राएँ अध्ययनों में इस्तेमाल हुई हैं और डॉक्टर से बात करने के लिए हैं। इन्हें नुस्खा न समझें।

सर्प्लीमेंट के तीन नियम
पहले जाँच, फिर सर्प्लीमेंट- खून की जाँच बताती है कि आपमें सचमुच किस चीज की कमी है।

डॉक्टर को सब कुछ बताएँ- कई सर्प्लीमेंट बीपी, दिल और खून पतला करने वाली दवाओं के साथ मिलकर गड़बड़ कर सकते हैं।

बीपी बढ़ाने वाली चीजों से बचें- मुलेटी और बहुत-से फ़ैट बर्नर तथा जिम के प्री-वर्कआउट पाउडर बीपी बढ़ाते हैं। बिना जाँच-परख वाली कुछ जड़ी-बूटी और भस्म की दवाओं में भारी धातुएँ भी पाई गई हैं, जो किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं। कोई भी सर्प्लीमेंट हार्ट अटैक और लकवे से वैसा बचाव नहीं करता, जैसा बीपी की दवाओं से साबित हुआ है।

एक बार दवा शुरू हुई तो क्या कभी बंद हो सकती है?—कभी-कभी हाँ, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में। ज्यादातर लोगों में हाई बीपी लंबी चलने वाली तकलीफ है और दवा सालों चलती है। इसकी वजह यह नहीं कि गोली की लत लग जाती है। लत नहीं लगती। दवा बंद करने पर बीपी इसलिए लौट आता है क्योंकि उसकी जड़ अब भी मौजूद है। जड़ बदल दें तो तस्वीर बदल सकती है। दवा की मात्रा अक्सर कम हो सकती है, और कभी-कभी दवा बंद भी हो सकती है, जब: वजन अच्छा-खासा घटे और घटा ही रहे, नमक और शराब कम हो जाएँ और कसरत रोज की आदत बन जाए, खराटों और नींद में साँस रुकने का इलाज हो जाए, थायरॉइड या किसी दूसरे बीमारी की छिपी गड़बड़ी ठीक हो जाए, बीपी बढ़ाने वाली कोई दवा बंद कर दी जाए।

सबसे अच्छी संभावना उन लोगों की है जिनका बीपी हल्का बढ़ा था, जो एक ही दवा पर हैं और जिनके दिल, किडनी या आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।
दो चेतावनियाँ- पहली: बीपी नॉर्मल आने पर खुद से दवा कभी बंद न करें। वह नॉर्मल इसीलिए है कि दवा काम कर रही है।
दूसरी: दवा अचानक कभी न छोड़ें। कुछ दवाओं को अचानक बंद करने से बीपी खतरनाक तरीके से उछल सकता है। दवा धीरे-धीरे, घर पर बीपी नापते हुए काम की जाती है, और उसके बाद भी नियमित जाँच जरूरी है, क्योंकि बीपी अक्सर कुछ महीनों में फिर बढ़ने लगता है। दवा और रहन-सहन एक-दूसरे की साथी हैं। बुनियाद जितनी मजबूत, गोलीयाँ उतनी कम और मात्रा उतनी हल्की।

तुरंत अस्पताल कब जाएँ?— अगर बीपी 180/120 या उससे ज्यादा हो और साथ में नीचे लिखी कोई भी तकलीफ हो, तो बिना देर किए इमरजेंसी में जाएँ: सीने में दर्द या जकड़न, साँस फूलना, अचानक तेज सिरदर्द, चेहरे, हाथ या पैर में कमजोरी, सुनपन या चेहरा एक तरफ लटकना, बोलने में दिक्कत, घबराहट भरी उलझन या बेहोशी, अचानक दिखना बंद होना या धुँधला दिखना, दौरा (झटके) पड़ना। ये इस बात के संकेत हैं कि दिल, दिमाग, आँख या किडनी पर सीधा हमला हो रहा है। ये लक्षण हों तो बीपी कुछ भी हो, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
बीपी 180/120 या ज्यादा, पर कोई तकलीफ नहीं- शांत बैठें और पाँच मिनट बाद दोबारा नापें। अगर तब भी उतना ही हो, तो उसी दिन अपने डॉक्टर से बात करें। बीपी को जबरदस्ती गिराने के लिए अपने मन से ज्यादा गोलीयाँ न खाएँ। बीपी का तेजी से गिरना भी नुकसान कर सकता है।
गर्भावस्था में और डिलीवरी के बाद के हफ्तों में- बीपी 140/90 या ज्यादा हो तो फ़ौरन डॉक्टर को बताएँ। बीपी 160/110 हो, या बढ़े हुए बीपी के साथ सिरदर्द, आँखों के आगे धुँधलपन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या अचानक सूजन हो, तो यह इमरजेंसी है।
बीपी लगातार 140/90 या ज्यादा- (घर पर 135/85) रहे तो यह इमरजेंसी नहीं है। फिर भी कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर डॉक्टर को दिखाएँ, महीनों तक न टालें।
वाद रखने की बात- हाई बीपी आम है, खामोश है और खतरनाक है। फिर भी यह उन बीमारियों में से है जिनसे सबसे आसानी से बचा जा सकता है और जिन्हें अटैक और लकवे से वैसा बचाव नहीं जानिए। पृष्ठिए कि वह बढ़ा क्यों है। खाने, नींद, चलने-फिरने और शांत मन की बुनियाद मजबूत कीजिए। खून की जाँच में जो कमी निकले, उसे पूरा कीजिए। और जब दवा की जरूरत हो तो बिना डर और बिना झिझक के लीजिए। मकसद सिर्फ मशीन पर अच्छा नंबर लाना नहीं है। मकसद है स्वस्थ नसों, मजबूत दिल और आने वाले कई दशकों तक साफ दिमाग।
यह लेख आम जानकारी के लिए है और आपके डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकता। कोई भी इलाज बदलने या सर्प्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

- सीएम ने चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि प्रदान किया
- मुख्यमंत्री ने कराया बच्चों का अन्नप्राशन, स्टॉल आदि का अवलोकन भी किया

समाचार सेन्टर संवाददाता

बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर की विकास यात्रा पर आधारित लघु फिल्म भी देखी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि प्रदान किया। सीएम ने बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। महिलाओं को फलों समेत पोषण की पोटली दी। उन्होंने यहां विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल आदि का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने कराया बच्चों का अन्नप्राशन- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर बच्चों का अन्नप्राशन

कराया। साथ ही महिलाओं को फलों समेत पोषण पोटली दी। उन्होंने यहां लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल आदि का भी अवलोकन किया। सभी से जनपदों में चल रहे विभागीय कार्यों की जानकारी भी ली।

सीएम के हाथों इन्हें मिला सम्मान- विकास यादव- उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना- लैपटॉप, मो. शादाब- उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना- लैपटॉप, किरन वर्मा- कस्टम हायरिंग सेंटर- चाबी, हिमांशु यादव- कस्टम हायरिंग सेंटर- चाबी, अजय कुमार पाल- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का



चेक, हसन रजा- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का चेक, गुफरान अंसारी- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख का

चेक,, किशना देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र, ननका देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र, उमिल्ला देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र, गुड़िया वर्मा/पिंकी- एनआरएलएम के तहत 45 लाख का चेक।

संगीता- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र, ननका देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र, उमिल्ला देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वीकृति पत्र, गुड़िया वर्मा/पिंकी- एनआरएलएम के तहत 45 लाख का चेक।

नानपारा-नेपालगंज रोड गुड्स शेड से पूर्ण रेक में माल की लोडिंग व अनलोडिंग सुविधा शुरू



समाचार सेन्टर संवाददाता

लखनऊ। व्यापार एवं उद्योग जगत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल ने नानपारा एवं नेपालगंज रोड स्टेशनों के गुड्स शेड को पूर्ण रेक के आवक एवं जावक माल यातायात के लिए खोल दिया है। इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र के व्यापारियों एवं माल ग्राहकों को बड़ी मात्रा में माल की आवाजाही के लिए सुगम और प्रभावी रेल परिवहन विकल्प उपलब्ध करना है। इसके अंतर्गत उर्वरक, नमक, सीमेंट, खाद्यान्न एवं रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) की लोडिंग एवं अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्ण रेक के माध्यम से व्यापारी एक साथ बड़ी मात्रा में माल मंगा अथवा भेज सकेंगे,

जिससे थोक व्यापार एवं औद्योगिक आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा होगी। नानपारा एवं नेपालगंज रोड गुड्स शेड की यह सुविधा विशेष रूप से नेपाल एवं भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार करने वाले कारोबारियों, उद्योगों एवं थोक माल ग्राहकों के लिए उपयोगी होगी। रेल के माध्यम से बड़े पैमाने पर माल की आवाजाही का विकल्प उपलब्ध होने से क्षेत्र में माल आपूर्ति को अधिक सुगम बनाए और व्यापारिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलेगी। इससे निर्माण सामग्री, कृषि एवं खाद्य क्षेत्र तथा अन्य संबंधित व्यवसायों को अपनी माल आवश्यकता के अनुसार रेल परिवहन का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, क्षेत्र में

माल की आवक-जावक बढ़ने से स्थानीय लॉजिस्टिक एवं परिवहन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गुड्स शेड पर माल की लोडिंग- अनलोडिंग के साथ हैडलिंग, भंडारण, परिवहन एवं अन्य संबद्ध लॉजिस्टिक सेवाओं की मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस प्रकार यह सुविधा केवल माल परिवहन को बेहतर बनाए तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्र की व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती प्रदान करेगी।

रेलवे प्रशासन ने नेपाल एवं सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारियों, उद्योगों तथा माल ग्राहकों से अपील की है कि वे अपनी व्यापारिक

नेपाल एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारियों को बड़े पैमाने पर माल परिवहन के लिए मिलेगा बेहतर रेल विकल्प

आवश्यकताओं के अनुसार नानपारा एवं नेपालगंज रोड गुड्स शेड की पूर्ण रेक सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएँ। व्यापारी बड़ी मात्रा में माल की आवक एवं जावक के लिए रेल परिवहन को अपने लॉजिस्टिक विकल्प के रूप में अपनाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल का यह प्रयास क्षेत्र में माल परिवहन की क्षमता को बढ़ाने, व्यापार को सुगम बनाने तथा नेपाल एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सेवा ही संस्कृति का हुआ नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन

समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। ललित कला विभाग,महात्मा गांधी कला विद्यापीठ एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (सांस्कृतिक मंत्रालय) क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के तत्वाधान में सेवा ही संस्कृति का नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन का शुभारंभ दिनांक 06/10/2026 को विभाग के सभागार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर संगीता घोष ने दीप प्रज्वलित कर किया। नाटक के माध्यम से देश में पिछले 15 वर्षों में घटित घटनाओं के बावजूद देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। इसी को अभिनय के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के



रूप में प्रोफेसर संगीता घोष ने कहा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सेवा ही संस्कृति नाटक प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारी घटनाएँ हुईं उसके बावजूद देश अपने विकास

पर अग्रसर है। इस नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार ललित कला विभाग के बी एफए, एमएफए तथा डिप्लोमा नृत्य के भावना मोर्य, अर्पिता केसरी, प्रियंका मिश्रा, प्रियल सेठ, राम भरत

चौहान, साक्षी सिंह, मान्या, प्रसून कुमार सिंह तथा मान्या प्रतिभाग किया। इस नाटक का कोरियोग्राफ राज कुमार साह ने किया। इस अवसर पर डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद, डॉ. मदन प्रसाद गुप्ता, डॉ रामराज, एस

एंजला, पद्मिनी मेहता, सौरभ दास, शालिनी कश्यप एवं विभाग के छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार विश्वकर्मा ने किया।

सभी 100 वार्डों में स्ट्रीट लाइट व नाइट स्वीपिंग की जांच करेंगे नोडल अफसर

समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। शहर की सड़कों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति परखने के लिए नगर निगम प्रशासन ने व्यापक जांच अभियान की रूपरेखा तैयार की है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए शहर के सभी 100 वार्डों के लिए तिथिवार नोडल अफसरों और आलोक विभाग (लाइटिंग विभाग) के कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर दी है। यह विशेष निरीक्षण अभियान सात से 19 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत अधिकारी शाम व रात के समय खुद सड़कों पर उतरकर वार्डों का धरातलीय जायजा लेंगे।

जांच के दौरान अधिकारी मुख्य व आंतरिक मार्गों पर लगी कुल लाइटों, बंद (अक्रियाशील) व पीली लाइटों की संख्या, साप्ताहिक मरम्मत टीम

नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश, सात से 19 अक्टूबर तक होगा वार्डों का धरातलीय निरीक्षण

की सक्रियता और लाइटों के ऑन-ऑफ होने की समयबद्धता को बारीकी से परखेंगे। इसके साथ ही वार्डों के अंधेरे वाले स्थानों (डार्क स्पॉट्स) को चिह्नित कर नई लाइटें लगाने का खाका तैयार किया जाएगा और नाइट स्वीपिंग में जुटे सफाई मित्रों की मौके पर उपस्थिति व सफाई के स्तर की जांच होगी। निरीक्षण के बाद अफसरों को दैनिक रिपोर्ट निगम के आईटी एक्सपर्ट विद्या प्रकाश दुबे को भेजनी होगी, जिसके आधार पर समेकित रिपोर्ट तैयार कर नगर आयुक्त और प्रभारी अधिकारी (आलोक) के सामने पेश की जाएगी। नगर आयुक्त का यह आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

5जी-6जी संचार की नई तकनीकों से खूबखू हुए ईसीई के विद्यार्थी



समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के आई ट्रिपल इ (IEEE) स्टूडेंट ब्रांच द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग के विद्यार्थियों हेतु मंगलवार को विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान का विषय 5जी एवं 6जी संचार के लिए

बहु-अभिगम तकनीकों रहा। इसमें विभाग के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। आभासी माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के विशेषज्ञ वक्ता डॉ. सौरभ दीक्षित, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तथा आईआईटी कानपुर एवं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे। उन्होंने वायरलेस

संचार प्रणालियों के विकास तथा वर्तमान एवं आगामी मोबाइल नेटवर्क में उन्नत बहु-अभिगम तकनीकों की भूमिका पर विद्यार्थियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक संचार व्यवस्था में अधिक गति और कम विलंबता वाले संचार के लिए नई तकनीकों का विकास आवश्यक है। 5जी के बाद 6जी

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के साथ ही कुम्भ मेला-2027 के कार्यों के लिए 81 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

समाचार सेन्टर संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के टनकपुर एवं बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किमी आन्तरिक मार्गों का निर्माण किये जाने हेतु 9.94 करोड़, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रांट के वैश्वनी मंदिर पुल के पास लालतपड़ से लेकर गोरखा बस्ती सागर आदि के घरों तक 02 किमी० सड़क का निर्माण किये जाने हेतु 1.37 करोड़, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के भूमिधारा से कुमालगांव खडण्डा एवं पुलिया निर्माण किये जाने हेतु 74.24 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत में 44.54 लाख तथा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत मझेड़ा में



प्राथमिक विद्यालय भूगांव से नाघर, कुमालता, स्यूसी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने हेतु 49.85 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत डाम क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिर का सुहृदीकरण किये जाने हेतु 1.62 करोड़, जनपद पिथौरागढ़ के गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 32.53 लाख, जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में शक्तिपीठ

भौनादेवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 98.79 के सापेक्ष 50.00 लाख तथा जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत की प्रतिमा स्थापित तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 79.74 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि 31.90 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार शाखा के अन्तर्गत कोटद्वार नगर की सनेह नगरीय पेजवाल योजना में सनेह मल्ली में नलकूप खनन उद्भव जलाशय निर्माण किये जाने हेतु 3.30 करोड़ तथा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत तौक भौरा फील्ड सिंचाई गूल का निर्माण किये जाने हेतु 44.13 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं

समाचार सेन्टर संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का



विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व हमारी संस्कृति एवं परम्परा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परम्परा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है।

वाराणसी में 25 को पीएम मोदी का युवाओं से संवाद, 30 हजार जेन-जी होंगे शामिल

वाराणसी (समाचार सेन्टर)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी में करीब 30 हजार Gen-Z युवाओं से संवाद कर सकते हैं। यह कार्यक्रम प्रस्तावित एंशर शो के दौरान होने वाले प्रमुख आयोजनों में शामिल होगा। 25 अक्टूबर को वाराणसी में एंशर शो का मुख्य समारोह प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना है।



ओटीएस के बाद भी सुस्ती पड़ेगी भारी, 15 नवंबर के बाद बकाएदार भवन स्वामियों पर कसेगा शिकंजा, होगी कुर्की

- शहर के 97,872 मकानों पर अटका है 298 करोड़ का टैक्स, 86 करोड़ की छूट के बावजूद करदाता बेपटवाह
- अब तक महज 2,476 लोगों ने जमा किए 3.96 करोड़ रुपये, नगर निगम ने थमाया आखिरी अल्टीमेटम
- नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की सख्त चेतावनी, समय सीमा बीतते ही सीधे होगी कुर्की और कानूनी कार्रवाई

समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। अगर आपने अब तक अपने मकान का बकाया टैक्स जमा

नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए! नगर निगम से मिलने वाली छूट का समय तेजी से निकल रहा है। इसके बाद नगर निगम की कोई भी रियायत काम नहीं आएगी, बल्कि सीधा शिकंजा कसा जाएगा। शासन के निर्देश पर लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की मियाद खत्म होते ही निगम बकाएदारों के घर कुर्की का नोटिस लेकर पहुंचेगा। नगर क्षेत्र के 97,872 भवनों पर इस समय ब्याज और सरचार्ज मिलाकर 298 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बकाया है। इसमें से करीब 86 करोड़ रुपये केवल सरचार्ज (व्याज) का है, जिसे सरकार ओटीएस के तहत पूरी तरह माफ कर रही है लेकिन इस बंपर छूट के बावजूद शहर के भवन स्वामी ढिलाई बरत रहे हैं। ओटीएस लागू हुए डेढ़ माह बीत चुके हैं, लेकिन 97 हजार से अधिक बकाएदारों में से महज 6,810 लोगों ने ही पोटेल पर पंजीकरण कराने की जहमत उठाई है। वहीं



इनमें से भी सिर्फ 2,476 भवन स्वामियों ने अपने भवन का कर 3.96 करोड़ रुपये का राजस्व जमा किया है। बाकी करदाता अब भी अंतिम तारीख के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जो उन्हें भारी पड़ सकता है।

पंजीकरण कराएं, 31 दिसंबर तक पाएं छूट का लाभ- नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि ओटीएस का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 15 नवंबर ही तय की गई है। इसके बाद किसी को दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी। जो भवन स्वामी 15 नवंबर तक अपना पंजीकरण करा लेंगे, उन्हें 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर ओटीएस का पूरा लाभ दिया

जाएगा, लेकिन यदि 15 नवंबर तक पंजीकरण ही नहीं कराया गया, तो ऐसे भवन स्वामियों को मूल बकाये के साथ पूरा सरचार्ज देना होगा। उन्होंने बताया कि बकाएदारों को एसएमएस और फोन कॉल के माध्यम से लगावार रिमाइंडर भेजकर सचेत भी किया जा रहा है ताकि समय रहते वह अपना पंजीकरण करा लें। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जो भवन स्वामी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कर जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मकान व संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में विधिक कार्यवाई से बचना है, तो तुरंत ओटीएस का लाभ उठाकर अपना टैक्स जमा करें।



संचार तकनीक संचार व्यवस्था को और अधिक उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को संचार प्रणालियों, संकेत प्रसंस्करण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा भविष्य की तकनीकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने

ज्ञान एवं कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। व्याख्यान के संबोधित करते हुए आई ट्रिपल इ कि वरिष्ठ सदस्य और निदेशक अशोका डॉ सारिका श्रीवास्तव ने आई ट्रिपल इ (IEEE) स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि तकनीक का विकास और प्रयोग समाज व मानव कल्याण के लिए होना चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन छात्रा हर्षिता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अनुजा सिंह ने किया। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष इं. प्रदीप कुमार वर्मा, इं.पवन कुमार सिन्हा, इं.ललित कुमार, इं.पंकज विश्वकर्मा, इं.सृष्टि सिंह सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

शिंजो आबे व मोदी की अटूट दोस्ती का जीवंत प्रतीक बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर



- 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' का लोकार्पण
- 25 साल के सेवा संकल्प पर काशी में भारत-जापान मैत्री का स्वर्णिम अध्याय, सीएम योगी और आकिए आबे ने किया स्मृति गलियारे का उद्घाटन
- जापान की पूर्व प्रथम महिला आकिए आबे हुई भावुक, बोलीं- पति जीवित होते तो आज खुद काशी खिंचे चले आते
- प्रदेश में 500 एकड़ में विकसित हो रही 'जापानी सिटी', सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देश रच रहे नया इतिहास: योगी आदित्यनाथ

समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कूटनीतिक संबंधों की ऐतिहासिक गवाह बन चुकी मोक्षनगरी काशी में बुधवार को भारत और जापान के अटूट रिश्तों का एक नया एवं जीवंत अध्याय लिखा गया। सिरा स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णीय शिंजो समेलन केंद्र में निर्मित 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' (स्मृति गलियारा) का भव्य उद्घाटन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्णीय शिंजो आबे की धर्मपत्नी आकिए आबे और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

यह गरिमामय समारोह उत्तर प्रदेश सरकार के 'सेवा संकल्प अभियान' (25 साल - नरेन्द्र मोदी: जन सेवा से देश सेवा) के अंतर्गत आयोजित किया गया। शिवलिंगाकार स्थापत्य कला से सुसज्जित और बाहरी दीवारों पर 108 एल्युमिनियम रुद्राक्षों से आच्छादित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बनी यह विशेष फोटो गैलरी दिसंबर 2015 में शिंजो आबे की ऐतिहासिक काशी यात्रा और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आत्मीय पलों की दुर्लभ तस्वीरों को संजोए हुए है।

आकिए आबे का भावुक संबोधन: काशी और क्योटो की साझेदारी का सपना हुआ साकार- समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जापान की पूर्व प्रथम महिला आकिए आबे ने अपनी काशी यात्रा और आबे मेमोरियल कॉरिडोर के लोकार्पण पर गहरा भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में जब मेरे पति बनारस आए थे, तब उन्होंने मां गंगा को बड़े ध्यान और श्रद्धा से देखा था। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं स्वयं काशी आऊं और इन पावन स्थलों को अपनी आंखों से देखूं। आज आबे मेमोरियल कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ मेरी वह इच्छा पूरी हो गई है। स्वर्णीय शिंजो आबे की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि अगर आज मेरे पति जीवित होते, तो इस सुंदर मेमोरियल कॉरिडोर को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते व वह जरूर कहते कि मैं भी वाराणसी जाऊंगा' और सचमुच आज वह यहां उपस्थित होते।

आकिए आबे ने रुद्राक्ष कन्वेंशन

सेंटर के निर्माण की पृष्ठभूमि साझा करते हुए बताया कि काशी और क्योटो-दोनों ही अति प्राचीन सांस्कृतिक शहर हैं। दोनों शहरों के बीच साझेदारी मजबूत करने के लिए वर्ष 2014 में 'काशी-क्योटो पार्टनर सिटी समझौता' हुआ था। इसके बाद जब शिंजो आबे भारत आए, तो काशी में एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि उनके विशेष आग्रह पर ही उनके पति ने इस भव्य केंद्र के लिए अनुदान स्वीकृत किया था।

रुद्राक्ष के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, भगवान शिव को समर्पित इस केंद्र का नाम 'रुद्राक्ष' स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। इसकी बाहरी दीवारों पर 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 108 की संख्या जापान के लोगों के लिए भी उतनी ही पवित्र और पूजनीय है, जितनी भारत में। जापान में नववर्ष की पूर्व

संध्या पर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाने की प्राचीन परंपरा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तार जोड़ती है।

भविव्य की तकनीक, 500 एकड़ में जापानी सिटी और ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव: योगी आदित्य नाथ- मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने भारत-जापान के आर्थिक व औद्योगिक संबंधों के नए युग का खाका प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्यरत हैं। अब यह साझेदारी केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित न रहकर सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, एंटीफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनिरल्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों तक विस्तार ले चुकी है। उन्होंने कहा, जापान के पास उच्च तकनीक (प्रिसिजन टेक्नोलॉजी) और अनुभव है, जबकि भारत के पास प्रतिभावान युवा ऊर्जा और

दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। जब दो महान नेताओं की मित्रता दो राष्ट्रों की रीढ़ बनती है, तब इतिहास रचा जाता है। अपनी हालिया जापान यात्रा का संस्मरण साझा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि फरवरी में मुझे जापान जाने का अवसर मिला था। टोक्यो और यामानाशी में जापानी कंपनियों के साथ हजारों करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार वाली मैग्नेट ट्रेन की यात्रा कर मैंने जापान की प्रिसिजन इंजीनियरिंग को करीब से देखा। जिस यामानाशी में आबे सान ने पीएम मोदी का स्वागत किया था, वही यामानाशी अब उत्तर प्रदेश का 'ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पार्टनर' है। अगस्त 2026 में यामानाशी के गवर्नर नोरिकोसुगु नागासाकी 200 से अधिक निवेशकों के साथ यूपी आए थे। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की जानकारी देते हुए उन्होंने

बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के निकट ग्रेटर नोएडा/इंटा क्षेत्र में 500 एकड़ में एक भव्य 'जापानी सिटी' विकसित की जा रही है, तथा 'इन्वेस्ट यूपी' में एक समर्पित 'यामानाशी डेस्क' स्थापित की गई है।

सुरप्रसिद्ध तुलसीदास जी की पंक्तियों से बताया सच्चे मित्र का अर्थ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत जापानी भाषा में

स्मृतियों को हमेशा के लिए बसा रही है। विशेष संयोग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक 25 वर्ष पहले, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जनसेवा की उनकी 25 वर्षों की इस स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर उनके प्रिय मित्र स्वर्णीय शिंजो आबे की स्मृति को समर्पित इस कॉरिडोर का उद्घाटन होना इससे सुंदर संयोग नहीं हो सकता। दोनों नेताओं की यह मित्रता पद या स्वार्थ पर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास पर आधारित थी। मित्रता की परिभाषा रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध चौपाई का उद्धरण दिया -निज दुख गिर सम रज करी जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ (अर्थात्, सच्चा मित्र वही है जो अपने पहाड़ जैसे बड़े दुख को धूल के कण के समान छोटा समझे और मित्र के धूल जितने छोटे दुख को भी पहाड़ जैसा बड़ा मानकर उसकी सहायता करे।)

सीएम योगी ने कहा कि आज की दुनिया में जहां रिश्ते नफा-नुकसान देखकर तय होते हैं, वहीं भारत और जापान के रिश्ते किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि गहराते विश्वास ('ट्रस्ट') पर टिके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अगस्त 2007 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए शिंजो आबे ने कहा था कि मजबूत भारत जापान के हित में है और मजबूत जापान भारत के हित में है। इसी ऐतिहासिक सोच के तहत 2014 में 'काशी-क्योटो' समझौता हुआ, 2015 में शिंजो आबे ने गंगा अरती के दर्शन किए, 2017 में अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन

परियोजना का शिलान्यास हुआ और 2018 में आबे सान ने प्रधानमंत्री मोदी को यामानाशी स्थित अपने निजी आवास पर आमंत्रित कर कूटनीति को पारिवारिक आत्मीयता दी। दिल्ली मेट्रो, वेस्टर्न समर्पित मालभाड़ा गलियारा (DFCC) और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) जैसे भारत के बुनियादी ढांचे की हर बड़ी छलांग में जापान एक विश्वसनीय साथी की तरह खड़ा रहा है।

संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तारों को जोड़ते हुए कहा, वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह गलियारा उस 'अमृत पर्व' की पहली सौगात है। जापान 'उगते सूरज की भूमि' (लैंड ऑफ द राइजिंग सन) है और उत्तर प्रदेश सूर्यवंश की भूमि (लैंड ऑफ द सन डायनेस्टी) है, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। इसके अलावा सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कोशाग्वी और सँकिया जैसे भगवान बुद्ध के पावन तीर्थ उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। इस प्रकार जापान की अगाध आस्था का मार्ग उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र उच्चस्तरिय प्रतिनिधिमंडल से और काशी के गणमान्य नागरिक एवं स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। संचालन अभिनव चतुर्वेदी ने किया।



समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में

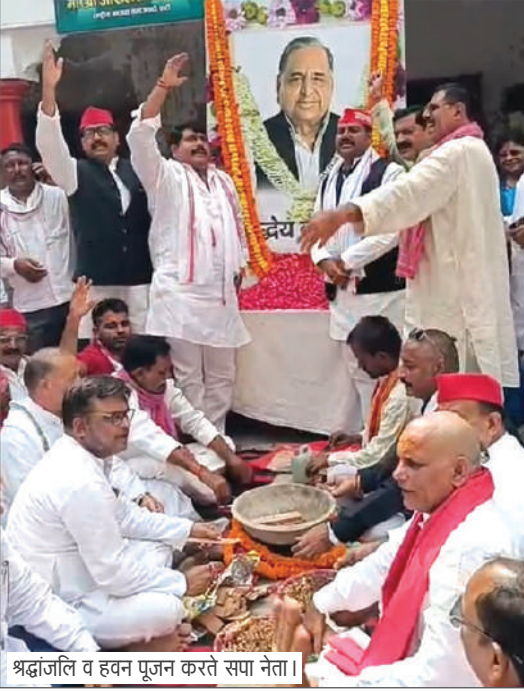
आईआईईट् स्टूडेंट चैप्टर, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टूडेंट ब्रांच और कंप्यूटर साइंस एंड

इंजीनियरिंग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में द एरा ऑफ गेमिफिकेशन एंड सीरियस गेम्स इन

चौथी पुण्यतिथि पर याद किये गये मुलायम सिंह यादव, दी श्रद्धांजलि

समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार में शनिवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर सप्ता कार्याकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और एक वैचारिक संगोष्ठी आयोजित कर उनके संघर्ष, विचारों एवं जनसेवा में किये गये योगदान को याद किया गया। इसके पश्चात हवन पूजन एवं शान्ति पाठ का कार्यक्रम नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशिप्रताप सिंह द्वारा कराया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि न्यायप्रिय राजनीति और समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ परम नेताजी की कमी सदैव महसूस होती रहेगी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय की स्थापना और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। शोषित, वंचित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। सभा का संचालन करते हुए प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने कहा कि



श्रद्धांजलि व हवन पूजन करते सभा नेता।

मुलायम सिंह ऐसे जननेता थे, जिन्होंने राजनीति को सत्ता के गलियारों तक सीमित ना रखकर गांव, गरीब किसान और आम आदमी के बीच पहुंचाया। उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर

खड़े व्यक्ति की आवाज को बुलंद किया तथा सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को मजबूती प्रदान किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने तथा संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने किया। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से अब्दुल समद अंसारी, आत्माराम यादव, समता पार्टी संयोजक शशि प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव विष्णु शर्मा, प्रदीप जायसवाल, महेंद्र पाल पिट्ट, अखिलेश मिश्रा, गणेश यादव, रामसिंह यादव, भीष्म नारायण सिंह, अखिलेश यादव, उमाकांत त्रिपाठी, उमा यादव, गोपाल पाण्डेय, पंचारी यादव एडवोकेट, कमलेश पटेल, धर्मेन्द्र यादव सिंद्धु, पुतुल यादव, दयाराम, हृदय शंकर गुप्ता, आलोक सौरभ, दिलशाद अहमद, रामकुमार यादव, जगू पाल, विद्या भारती, मनोज यादव, शिव प्रसाद गौतम, संजय पहलवान, राजेंद्र यादव, राम सिंह भारद्वाज, सचिन प्रजापति, धर्मवीर पटेल, दिनेश गायक, रामकिंकर पटेल, कन्हैयालाल, महेंद्र बच्चन, रमापति राजभर, राजू यादव, विनोद सिंह पटेल, जवाहर लाल, आशीष यादव, अयाज खान, सुभाष यादव, विनोद शुक्ला आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।

गेमिफिकेशन व शैक्षणिक खेलों पर अशोका में कार्यशाला सम्पन्न



एजुकेशन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीएसई विभाग के सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आधुनिक शिक्षा में खेल आधारित शिक्षण की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की।

कार्यशाला में बेनेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विवेक कुमार ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि गेमिफिकेशन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक, संवादपरक और प्रभावी बनाया जा

सकता है। शैक्षणिक खेल विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के साथ उनकी तार्किक क्षमता, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को

विकसित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने आधुनिक शिक्षा में इंटरैक्टिव गेम आधारित लर्निंग की बढ़ती भूमिका और इसके व्यावहारिक उपयोगों पर भी प्रकाश

प्रभावी और विद्यार्थी केंद्रित बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रयोग विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने में सहायक है। कार्यक्रम का संचालन यूबिका श्रीवास्तव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डीन सीएसई डॉ. एल.एस. मोहन ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सीएसई विभागाध्यक्ष डॉ. अनुभव प्रसाद, एआई एंड एमएड विभाग की प्रमुख डॉ. प्रीति कुमारी, बीसीए विभागाध्यक्ष इ.प्रदीप भंडारी, डीएस विभागाध्यक्ष इ.अभय मोहन और इ.विभाषा शंकर सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

गंगा घाटों पर सिल्ट सफाई की निगरानी के लिए अफसर तैनात

नगर आयुक्त ने तय की अधिकारी-कर्मचारी की घाटों की सीढ़ियों व प्लेटफॉर्म से गाद हटाकर त्वरित निस्तारण करने जिम्मेदारी



समाचार सेन्टर संवाददाता

वाराणसी। बाढ़ का पानी कम होते ही नगर निगम ने गंगा घाटों पर सफाई की व्यवस्था कर कार्योचना तैयार कर ली है। इस क्रम में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गंगा घाटों पर सिल्ट (गाद) सफाई कार्य की नियमित निगरानी के लिए अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी है। आदिकेशव घाट से लेकर रविदास घाट व रामघाट तक सभी 85 गंगा घाटों को अलग-अलग जोन और क्लस्टर में बांटकर पर्यवेक्षणिय व नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है। पर्यवेक्षणिय अधिकारियों को प्रतिदिन अपने आवंटित घाट का निरीक्षण कर ऑफिसर्स ग्रुप में जियोटेग फोटो शेयर करनी होगी।



नगर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर तीन दिनों के भीतर कार्य की प्रगति आख्या प्रस्तुत करें। सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने घाटों की सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश कुमार मिश्रा, विनोद कुमार गुप्ता,

पवन कुमार गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव, जोनल अधिकारी इन्द्र विजय, मनोज कुमार सिंह, मृत्युन्जय नारायण मिश्रा, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी संदीप भार्गव, जोनल स्वच्छता अधिकारी श्रित्तिज मिश्रा, राजीव कुमार और संयुक्त नगर आयुक्त कृष्णचंद्र को विभिन्न घाटों का प्रभार सौंपा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है

कि घाटों की सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म से गाद को पूरी तरह साफ कराया जाए। निकाली गई सिल्ट को घाटों पर जमा छोड़ने के बजाय तत्काल उठाकर तय स्थलों पर निस्तारित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

स्वामी/ प्रकाशक/ मुद्रक
अक्षय कुमार राय द्वारा
स्टेट मीडिया प्रिंटर्स, आराजी नं.-
661, मौजा-तरना, परगना-शिवपुर,
वाराणसी से मुद्रित एवं कोदोपूर,
पॉवर हाउस बुकिंग्स, वाराणसी-
221101 से प्रकाशित।
समादक
अक्षय कुमार राय
अपर.एन.आई. संख्या
UPBIL/2025/91151
दूरभाष :
9818735521, 9311729307
समाचार पत्र में प्रकाशित उतरदायी
समाचारों के लिये समस्त विवाद
वाराणसी न्यायालय के अधीन होंगे।